तमिलनाडु राज्य आदि

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य।

अप्रैल 26, 1991

[एन.एम. कासलीवाल, एम.एम. पुंछी और आर.एम. सहाय, जे.जे.]

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956: उ.धा. 3.5.11. अधिसूचना दिनांक 2.6.1990-कावेरी जल विवाद अधिकरण-अंतरिम राहत के लिए आवेदन-क्या विचारण और अनुदान का क्षेत्राधिकार है।

भारत का संविधान: अनुच्छेद 262-अंतरराज्यीय नदियों के संबंध में विवादों का न्यायनिर्णयन-संसद द्वारा बनाया जाने वाले कानून-सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार-बहिष्करण-क्या उत्पन्न होता है।

वैधानिक व्याख्या: क़ानून की व्याख्या करने और वैधानिक न्यायाधिकरण के पैरामीटर, दायरे, शक्ति और क्षेत्राधिकार तय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति।

तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 6.7.1986 को धारा 3 अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत केंद्र सरकार को एक शिकायत इस आधार पर भेजी कि कर्नाटक राज्य द्वारा की गई कार्यकारी कार्रवाई से उसके हित पूर्वाग्रहपूर्ण और हानिकारक रूप से प्रभावित हो रहे थे और उस

राज्य द्वारा संबंधित समझौतों की शर्तों को लागू करने में विफलता के कारण कावेरी नदी के जल का उपयोग, वितरण और नियंत्रण।

केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 2.6.1990 द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया और अंतर-राज्य नदी कावेरी से उभरने वाले विवादों के न्यायनिर्णयन आैर तमिलनाडु राज्य द्वारा दी गई दिनांक 6.7.1986 की शिकायत से उभरी उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के निपटारे के लिए इसे भेजा।

संदर्भ के लंबित रहने के दौरान तमिलनाडु सरकार ने अधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई कि कर्नाटक राज्य को कावेरी नदी के पानी को 31.5.1972 तक उसके द्वारा जब्त या उपयोग की गई सीमा से अधिक जब्त या उपयोग न करने का निर्देश दिया जाए, जैसा कि बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय सिंचाई और बिजली मंत्री द्वारा सहमति हुई थी; और कर्नाटक राज्य को कावेरी बेसिन में कोई भी नई परियोजना, बांध, जलाशय, नहर आदि शुरू करने और/या ऐसे किसी भी काम को आगे बढ़ाने से रोका जाए।

8.9.1990 को केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी ने अंतरिम आदेश के लिए एक आवेदन दायर किया जिसमें कर्नाटक और केरल राज्यों को सितंबर से मार्च के महीनों के दौरान 9,355 टी.एम.सी. पानी जिस पर पहले ही सहमति हो चुकी है, को मुक्त करने का निर्देश दिया गया।

तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक राज्य को कम से कम 20 टी.एम.सी. पानी पहली किस्त के रूप में जारी करने का निर्देश देने के लिए एक और आकस्मिक याचिका दायर की, जिस पर पहले आवेदन पर अंतिम आदेश होना लंबित था क्योंकि सांबा फसल को मेट्टूर जलाशय में अतिरिक्त आपूर्ति के बिना अनुरक्षित नहीं किया जा सकता था।

कर्नाटक और केरल राज्यों ने आवेदनों का विरोध किया और प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं कि अधिनियम के तहत गठित अधिकरण के पास सीमित क्षेत्राधिकार था, जिसमें केवल वे शक्तियां थीं जो अधिनियम के तहत उसे प्रदान की गई थीं और कानून का कोई प्रावधान नहीं था जो अंतरिम राहत देने के लिए उसे अधिकारिता प्रदान करता हो।

अधिकरण ने माना कि वह केवल 'जल विवाद' या उन विवादों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत था जो उसे संदर्भित किए गए थे, और तमिलनाडु राज्य द्वारा की गई शिकायत दिनांक 6.7.1988 के अनुसार तमिलनाडु राज्य द्वारा किए गए अनुरोध की तारीख के बाद साल-दर-साल कर्नाटक सरकार द्वारा पानी छोड़ने के संबंध में एक अंतरिम विवाद का संदर्भ नहीं दिया जा सका, वह अंतरिम राहत की प्रार्थना पत्र विचार नहीं कर सकता, जब तक कि उससे संबंधित विवाद को विशेष रूप से संदर्भित नहीं किया गया हो। आवेदनों को संधारणीय नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।.

तमिलनाडु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी द्वारा इस न्यायालय में की गई अपीलों में, प्रतिवादी राज्यों कर्नाटक और केरल ने आपत्ति जताई कि इस न्यायालय के पास अनुच्छेद 262 के रूप में अधिकरण के विवादित आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। संविधान में स्पष्ट रूप से इस संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा तय किए जाने वाले अंतर-राज्यीय नदियों के पानी से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए प्रावधान किया गया है।

अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि वे किसी भी विवाद के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय में नहीं आए हैं जो पहले से ही अधिकरण के समक्ष लंबित है, लेकिन उनकी शिकायत केवल इस हद तक है कि अधिरकण ने गलत निर्णय लिया है कि उसके पास किसी भी अंतरिम राहत के आवेदन के मामले पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि संदर्भ में इस तरह के विवाद का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस न्यायालय के पास अधिनियम के तहत अधिकरण की शक्तियों के दायरे को तय करने का अधिकार क्षेत्र है और यदि अधिकरण ने गलत तरीके से न्यायाधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, यह न्यायालय इसे सही करने और अधिकरण को ऐसे आवेदन पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए सक्षम है।

इस सवाल पर कि क्या: (1) इस न्यायालय के पास अधिनियम के तहत अधिकरण की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, (2) अंतरिम राहत के लिए आवेदनों में प्रार्थनाएं अधिकरण को संदर्भित विवाद के तहत शामिल थीं, और (3) अधिकरण के पास अंतरिम राहत के लिए आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया: (न्यायालय द्वारा, पर. कासलीवाल, जे.) 1. संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को यह प्रावधान करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत किया गया है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय, ना ही कोई अन्य न्यायालय राज्य नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। उपरोक्त विवाद से संबंधित अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण को भेजा गया विवाद और इस तरह इस न्यायालय के पास अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए और अधिकरण के समक्ष लंबित विवाद के गुण-दोष तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। [509 सी-डी]

2. वैधानिक अधिनियम के अर्थ को आधिकारिक रूप से निर्धारित करने और किसी क़ानून के तहत गठित किसी भी निकाय या अधिकरण के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने का कार्य केवल न्यायपालिका

का ही है। कावेरी जल विवाद अधिकरण अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण था और इस न्यायालय को उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता होने के नाते अधिकरण की शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र, मापदंडों, दायरे को तय करने का अधिकार और अधिकार क्षेत्र था। इस न्यायालय के पास न केवल शक्ति थी, बल्कि यह निर्णय लेने का दायित्व भी था कि अधिनियम के तहत अधिकरण के पास अंतरिम राहत के लिए किसी भी आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र है या नहीं, जब तक कि वह अंततः उसके द्वारा संदर्भित विवाद का फैसला नहीं कर लेता। [509 ई-एफ; 511 ई-एफ]

संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य, [1983] 1 एससीआर 1000 पृष्ठ 1029 और केहर सिंह और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, [1989] 1 एससीसी 204 पृष्ठ 214, अनुसरण किया गया।

3. दिनांक 2.6.1990 के संदर्भ आदेश द्वारा, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 6.7.1986 से उत्पन्न अंतर-राज्य नदी कावेरी से संबंधित जल विवादों को अधिकरण को संदर्भित किया था। इस प्रकार पत्र दिनांक 6.7.1986 से उभरे सभी विवादों को अधिकरण को भेजा गया था। अधिकरण द्वारा शिकायत के उस अंश को न पढ़कर एक

गंभीर गलती की गई, जिसमें तमिलनाडु राज्य तत्काल राहत का दावा कर रहा था, क्योंकि साल-दर-साल, मेट्टूर में वसूली तेजी से गिर रही थी और उनके बेसिन के अयाकट में हजारों एकड़ जमीन परती रहने के लिए मजबूर थी। इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि समाधान में अत्यधिक विलंब हो रहा है। इस विवाद का फायदा कर्नाटक सरकार द्वारा उठाया जा रहा था और नई परियोजनाओं में उनकी नहर प्रणालियों और उनके अयाकट का विस्तार किया जा रहा था और हर दिन की देरी से उनकी मौजूदा सिंचाई को होने वाली क्षति बढ़ रही थी। इस प्रकार अधिकरण का यह मानना स्पष्ट रूप से गलत था कि केंद्र सरकार ने कोई अंतरिम राहत देने के लिए कोई संदर्भ नहीं दिया था। [514 डी-ई; 515 सी-डी]

4. गुण-दोष के आधार पर किसी भी अंतरिम राहत के लिए अपीलकर्ताओं के मामले के बावजूद, अधिकरण के समक्ष उनके आवेदनों में उनके द्वारा मांगी गई राहत स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5 के तहत संदर्भित विवाद के दायरे में आती है और अधिकरण को गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। [515 ई; 516 बी]

5. अधिकरण ने यह नहीं माना कि उसके पास अंतरिम राहत देने के लिए कोई आकस्मिक और सहायक शक्तियां नहीं थीं, लेकिन उसने इस आधार पर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उसमें

मांगी गई राहतें केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित नहीं की गई थीं। उस दृष्टि से, मौजूदा मामले में इस बड़े सवाल पर फैसला करना जरूरी नहीं है कि क्या अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित अधिकरण के पास कोई अंतरिम राहत देने की कोई शक्ति है या नहीं। [515 ई-एफ]

तमिलनाडु कावेरी नीरप्पासन विलाइपोरुलगल विवासयिगल नालौरीमल पाधुगप्पु संगम बनाम भारत संघ एवं अन्य, **[1990] 3 एससीसी 440, संदर्भित।**

फ्रांसिस बेनियन द्वारा 'वैधानिक व्याख्या', **(पृष्ठ 53 और 548)** का उल्लेख किया गया है।

पर. सहाय, जे.:

संवैधानिक व्यवस्था के तहत किसी क़ानून के तहत बनाए गए किसी भी अधिकरण या प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र, शक्ति और सीमाओं को निर्धारित करना इस न्यायालय की प्राथमिक ज़िम्मेदारियों में से एक है। [516 सी]

6 जुलाई, 1986 के पत्र के निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर आपत्तियां हैं। हालाँकि, इस पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है क्योंकि गहन संवैधानिक और कानूनी महत्व के मुद्दे के रूप में जो मुद्दा शुरू हुआ वह तब समाप्त हुआ जब कर्नाटक और केरल राज्य ने अपने वकील के माध्यम

से कहा कि वे अंतरिम निर्देशों के लिए आवेदनों का गुण-दोष के आधार पर निर्धारण के लिए सहमत है। [516 सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1991 की सिविल अपील संख्या 303-304, 2036।

कावेरी जल विवाद अधिकरण 1990 के सी.एम.पी. सं. 4,9 और 5 के निर्णय व आदेश दिनांक 5.1.1991 से

एम. चंदर शेखरन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, के. परासन, एफ.एस. नरीमन, डॉ. वाई.एस. चितले, एस.एस. जावली, ए.एस. नांबियार, पी.एस. पोटी, सी. शिवप्पा, एम.एस. गणेश, वी. कृष्णमूर्ति, पी.के. मनोहर, श्रीमती एस. वासुदेवन, एम. वीरप्पा, मोहन कटारकी, अतुल चितले, के.एच. नोबिन सिंह, टी.टी. कुन्हिकन्नन, श्रीमती सुषमा सूरी और ए.के. श्रीवास्तव उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

कासलीवाल, जे. एस.एल.पी. (सी) नंबर 4991 डी 1991 में विशेष अनुमति याचिका प्रदान की गई।

विशेष अनुमति प्रदान करके ये अपीलें कावेरी जल विवाद अधिकरण के 5 जनवरी, 1991 के आदेश के विरुद्ध निर्देशित की गई हैं। उपरोक्त अपीलें सिविल विविध याचिका (संक्षेप में 'सी.एम.पी.) संख्या 4 और 9 1990 तमिलनाडु सरकार और सी.एम.पी. द्वारा आैर 1990 की संख्या 5,

केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के संबंध में तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की सरकारों द्वारा दायर की गई हैं और अधिकरण द्वारा 5 जनवरी, 1991 के एक सामान्य आदेश से खारिज कर दी गई।

चूंकि इन मामलों में कानून के समान प्रश्न उठते हैं, हम तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर किये गये सी.एम.पी. के तथ्यों को बताएंगे। तमिलनाडु सरकार ने 6 जुलाई, 1986 को इस आधार पर एक शिकायत दर्ज की कि तमिलनाडु राज्य और उसके निवासियों (विशेष रूप से कावेरी डेल्टा के किसानों) के हित कार्यकारी कार्रवाई से पूर्वाग्रहपूर्ण और हानिकारक रूप से प्रभावित हुए हैं और हो रहे हैं। कर्नाटक के ऊपरी रिपेरियन राज्यों द्वारा उठाए जाने का प्रस्ताव और कावेरी नदी के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित समझौतों की शर्तों को लागू करने में उस राज्य की विफलता। उक्त शिकायत अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार को की गई थी।

केंद्र सरकार ने अधिसूचना दिनांक 2.6.1990 द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया और निम्नलिखित संदर्भ आदेश पारित किया:

क्रमांक 21/1/90-डब्ल्यूडी

भारत सरकार (भारत सरकार)

जल संसाधन मंत्रालय

(जल संसाधन मंत्रालय)

नई दिल्ली, 2 जून 1990

संदर्भ

अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निर्णय के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण को संदर्भित करती है, जल अंतरराज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी से संबंधित विवाद, तमिलनाडु सरकार के पत्र संख्या 17527/के2/82-110 दिनांक 6 जुलाई 1986 से उभरे हैं (प्रतिलिपि संलग्न)।

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार

एवं नाम से

(एम.ए. चिताले)

सचिव, (जल संसाधन)

अध्यक्ष,

कावेरी जल विवाद अधिकरण,

नई दिल्ली।

उपरोक्त संदर्भ के लंबित रहने के दौरान तमिलनाडु सरकार ने सी.एम.पी. 1990 की संख्या 4 दायर किया आैर प्रार्थना की गई है कि

कर्नाटक राज्य को कावेरी नदी के पानी को 31.5.1972 को उनके द्वारा जब्त या उपयोग की गई सीमा से अधिक जब्त या उपयोग न करने का निर्देश दिया जाए, जैसा कि बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सिंचाई और बिजली के केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। आगे प्रार्थना की गई कि कर्नाटक राज्य को कोई भी नया कार्य परियोजनाओं, बांधों, जलाशयों, नहरों आदि, और/या कावेरी बेसिन में परियोजनाओं, बांधों, जलाशयों, नहरों आदि के निर्माण को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए एक आदेश पारित किया जाए।

8.9.1990 को सी.एम.पी. 1990 की संख्या 5 केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अंतरिम आदेश की मांग की गई थी, जिसमें कर्नाटक और केरल राज्यों को पहले से सहमत पानी 9.355 टी.एम.सी. सितंबर से मार्च के महीनों के दौरान छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

तमिलनाडु सरकार ने एक और आकस्मिक याचिका सी.एम.पी. 1990 की संख्या 9 दायर की, जिसमें कर्नाटक राज्य को कम से कम 20 टी.एम.सी. पानी पहली किस्त के रूप में पानी की आपूर्ति हेतु जारी करने का निर्देश चाहा, जब तक 1990 की संख्या 4 सी.एम.पी. अंतिम आदेश के लिए लंबित है। यह याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई थी कि मेट्टूर

जलाशय में अतिरिक्त आपूर्ति के बिना सांबा की फसल को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

उपरोक्त सभी आपराधिक फौजदारी याचिकाआेंं पर कर्नाटक राज्य और केरल राज्य द्वारा गुण-दोष के साथ-साथ प्रारंभिक आपत्ति पर भी विरोध किया गया था कि अधिकरण के पास कोई अंतरिम राहत देने के लिए इन याचिकाओं पर विचार करने की कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं था। प्रारंभिक आपत्ति इस आधार पर थी कि अधिनियम के तहत गठित अधिकरण के पास सीमित क्षेत्राधिकार था। इसमें सामान्य सिविल न्यायालय की तरह कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं थी। इसके पास केवल वही शक्तियाँ थीं जो अधिनियम के तहत इसे प्रदान की गई थीं और कानून का कोई प्रावधान नहीं था जो किसी भी अंतरिम राहत देने के लिए अधिकरण को अधिकृत या कोई क्षेत्राधिकार प्रदान करता हो। ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक राज्य और केरल राज्य की ओर से उठाई गई आपत्ति को बरकरार रखा और जिसके परिणामस्वरूप 5 जनवरी, 1991 के अपने आदेश द्वारा आदेश दिया गया कि अधिकरण अंतरिम राहत देने के लिए आवेदनों पर विचार नहीं कर सकता है और आपराधिक फौजदारी याचिका संख्या 4, 5 और 9 को कानून में समर्थन योग्य नहीं माना गया और इस तरह खारिज कर दिया गया। अधिकरण के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर ये अपीलें तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी द्वारा दायर की गई हैं।

डॉ. वाई.एस. चितले, प्रतिवादी कर्नाटक राज्य की ओर से उपस्थित होकर आपत्ति जताई कि इस न्यायालय के पास ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 262 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अंतर-राज्यीय नदियों के पानी से संबंधित विवादों के निर्णय के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी अनुच्छेद 262 के खंड (2) में आगे प्रावधान किया गया है कि संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा, जैसा कि खंड (1) में संदर्भित है।

यह प्रस्तुत किया गया कि अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 संसद द्वारा अंतर-राज्यीय नदी और नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 11 निम्नानुसार प्रदान की गई है

> "किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय के पास किसी जल विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा, ना ही

अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें जिसे इस अधिनियम के तहत एक अधिकरण को भेजा जा सकता है।"

इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त धारा 11 ने स्पष्ट रूप से न केवल किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी छीन लिया है।

दूसरी ओर विद्वान वकील श्री के. परासरन उपस्थित हुए तमिलनाडु राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 11 के प्रावधान सपठित अनुच्छेद 262 संस्था ने केवल सर्वोच्च न्यायालय या किसी के क्षेत्राधिकार को किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल का वितरण या नियंत्रण व उपयोग के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का निर्णय करने के लिए अन्य न्यायालय बाहर रखा। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता किसी भी विवाद के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए इस माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आए हैं जो पहले से ही ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है। अपीलकर्ता की शिकायत केवल इस हद तक है कि ट्रिब्यूनल ने गलत निर्णय लिया कि उसके पास किसी भी अंतरिम आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इस तरह के विवाद को केंद्र सरकार द्वारा किए गए संदर्भ में संदर्भित नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के पास अधिनियम के तहत अधिकरण की शक्तियों का दायरा तय करने का अधिकार क्षेत्र है और यदि

न्यायाधिकरण ने अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से गलती से इनकार कर दिया है, तो यह न्यायालय इसे सही करने और निर्देश देने के लिए सक्षम है कि अधिकरण ऐसे आवेदन पर विचार करेगा और गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय करेगा।

उपरोक्त विवाद को समझने के लिए संविधान के अनुच्छेद 262 और अधिनियम की धारा 11 का उल्लेख करना उचित होगा जो इस प्रकार है:

अनुच्छेद 262-अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन:

(1) संसद कानून द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन का प्रावधान कर सकती है।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा जैसा कि खंड (1) में संदर्भित है।

धारा 11:

"किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही किसी अन्य अदालत के पास किसी भी जल विवाद

के संबंध में अधिकार क्षेत्र होगा या उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिसे इस अधिनियम के तहत ट्रिब्यूनल को भेजा जा सकता है।"

उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि संविधान में किसी भी बात के बावजूद, संसद कानून द्वारा यह प्रावधान करने के लिए अधिकृत है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय उपयोग, किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल का वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल को भेजा गया विवाद उपरोक्त विवाद से संबंधित है और इस प्रकार इस न्यायालय के पास अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए और ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित विवाद के गुण-दोष तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालाँकि, इन अपीलों में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाया गया विवाद यह है कि उन्होंने विवाद के अंतिम निस्तारण तक आपातकाल के आधार पर अंतरिम राहत देने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए थे और ट्रिब्यूनल ने गलत माना कि उसके पास इस पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। वही ट्रिब्यूनल संसद द्वारा बनाए गए एक अधिनियम के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है और इस न्यायालय के पास ट्रिब्यूनल के मापदंडों, दायरे, प्राधिकरण और अधिकार क्षेत्र को तय करने का अधिकार क्षेत्र है। यह न्यायपालिका है यानी केवल अदालतों के पास वैधानिक अधिनियम के अर्थ को आधिकारिक रूप से निर्धारित करने

और क़ानून के तहत गठित किसी भी निकाय या न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने का कार्य है। फ्रांसिस बेनियन ने अपनी पुस्तक 'वैधानिक व्याख्या' के पृष्ठ 53 और 548 में इस मामले पर इस प्रकार विचार किया है:

पी. 53

"ब्रिटिश संविधान के तहत, संसदीय अधिनियम के अर्थ को आधिकारिक रूप से निर्धारित करने का कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया है। रिचर्ड बर्न के शब्दों में उनके पास अधिनियमों की व्याख्या है, जिसे 'किसी अन्य अर्थ में' व्याख्या नहीं किया जाना चाहिए यह वास्तव में और उचित रूप से उनका प्रदर्शन है'। यह प्रासंगिक कानून को उसके समक्ष मामले के तथ्य पर लागू करने के न्यायालय के सामान्य कार्य का एक पहलू है, इसलिए, प्रारंभिक बिंदु इस फ़ंक्शन पर विचार करना है।"

"किसी अधिनियम के कानूनी अर्थ की घोषणा करना अकेले अदालत का कार्य है। यदि कोई अन्य (जैसे कि प्रावधान का मसौदा तैयार करने वाला) यह बताने का इरादा रखता है कि कानूनी अर्थ क्या है तो अदालत इस संबंध में

इसके संवैधानिक क्षेत्र पर अतिक्रमण पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया देगी।

संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य, [1983] 1 एससीआर 1000 पृष्ठ 1029 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "कोई भी संसद के लिए नहीं बोल सकता है और संसद कभी भी न्यायालय के समक्ष नहीं होती है। संसद द्वारा वह कहने के बाद जो वह कहना चाहती है, केवल न्यायालय ही वह कह सकता है जो संसद कहना चाहती थी और कोई नहीं। एक बार जब कोई क़ानून संसद भवन से निकल जाता है, तो न्यायालय एकमात्र प्रामाणिक आवाज़ है जो संसद को प्रतिध्वनित (व्याख्या) कर सकती है। यह न्यायालय क़ानून की भाषा और अन्य अनुमेय सहायता के संदर्भ में करेगा। कार्यकारी सरकार न्यायालय के समक्ष संसद द्वारा कही गई बातों के बारे में अपनी समझ रख सकती है या वे जो कहना चाहते थे या जो वे सोचते हैं कि संसद का उद्देश्य था और वे सभी तथ्य और परिस्थितियाँ जो उनके विचार में कानून बनाने का कारण बनीं। जब वे ऐसा करते हैं, तो वे संसद के लिए नहीं बोलते हैं। संसद के

किसी भी कार्य को समझ या कार्यकारी सरकार द्वारा संसदीय इरादे की गलतफहमी या क्योंकि उनके (सरकार के) प्रवक्ता प्रासंगिक परिस्थितियों को सामने नहीं लाते हैं बल्कि खोखले और आत्म-पराजित हलफनामों में लिप्त रहते हैं। वे ऐसा नहीं करते हैं और वे संसद को बाध्य नहीं कर सकते हैं। कानून की वैधता का आकलन केवल राज्य की ओर से दायर किए गए हलफनामों से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन सभी प्रासंगिक परिस्थितियों से किया जाना चाहिए जो अंततः न्यायालय को मिल सकती हैं और विशेष रूप से विधायिका ने जो कहा है उससे क्या पता लगाया जा सकता है। हमने उन तथ्यों का उल्लेख किया है जो हमें मिले थे और हमें नहीं लगता कि अनुच्छेद 14 द्वारा गारंटीकृत अधिकार का कोई उल्लंघन हुआ है।

केहर सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1989] 1 एससीसी 204 पृष्ठ 214, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा:

"बहस के दौरान, अगला सवाल उठाया गया कि क्या न्यायिक समीक्षा संविधान की धारा 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश की जांच तक फैली हुई है। शुरुआत में हमें लगता है कि यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि

हम राष्ट्रपति की शक्ति के क्षेत्र और दायरे के प्रश्न तक ही सीमित हैं, न कि इस प्रश्न के साथ कि क्या इसका वास्तव में गुण-दोष के आधार पर प्रयोग किया गया है। वास्तव में, हमारा मानना है कि मारू राम बनाम भारत संघ में परिभाषित सख्त सीमाओं को छोड़कर राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। यह निर्धारित करने का कार्य कि क्या संवैधानिक या वैधानिक पदाधिकारी का कार्य संवैधानिक या विधायी शक्ति प्रदान करने के अंतर्गत आता है, या शक्ति के पूर्ण आयाम की गलत सराहना पर न्यायालय का मामला होने से आत्म-इनकार द्वारा दूषित है ।"

कावेरी नदी से संबंधित विवाद में ही संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक आवेदन तमिलनाडु कावेरी नीरप्पासन विलाइपोरुलगल विवासयिगल नाला उरीमल पाधु-गप्पु संगम द्वारा दायर किया गया था, जिसे तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी कहा गया था और इस न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि अधिनियम की धारा 4 के तहत विवाद को संदर्भित करने के लिए भारत संघ को निर्देश दिया जाए और तमिलनाडु कावेरी नीरप्पस्ना विलाइपोरुलगल विवासयी-गल नालौरीमल पाधुगप्पु संगम बनाम भारत संघ और अन्य, [1990] 3 एससीसी 440 में इस न्यायालय ने याचिका की

अनुमति दी और केंद्र सरकार को अपने वैधानिक दायित्व को पूरा करने और जल विवाद के निर्णय के लिए एक उपयुक्त अधिकरण के गठन को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

इस प्रकार, हम मानते हैं कि यह न्यायालय अंतर-राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याता है और अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण की सीमाएं, शक्तियां और अधिकार क्षेत्र तय करने का अधिकार रखता है। इस न्यायालय के पास न केवल शक्ति है, बल्कि यह निर्णय लेने का दायित्व भी है कि ट्रिब्यूनल के पास अधिनियम के तहत किसी भी अंतरिम आवेदन पर तब तक विचार करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार है या नहीं, जब तक कि वह अंततः उसके द्वारा संदर्भित विवाद का फैसला नहीं कर लेता। इस प्रकार डॉ. वाई.एस.चितले द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं है।

अब हम इन अपीलों में गुण-दोष के आधार पर उठाए गए विवादों की जांच करेंगे। ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि अंतरिम राहत के लिए इन विविध याचिकाओं पर विचार करना उसके अधिकार क्षेत्र में है। सबसे पहले, इस कारण से कि जब ट्रिब्यूनल अंतरिम राहत देने की शक्तियों का प्रयोग करता है तो यह केवल पूर्व-जैसा कि अंतरिम राहतों ने प्रार्थना की, 'आकस्मिक और सहायक शक्तियों' का हवाला देते हुए जल विवाद से उत्पन्न होने के लिए जिसे ट्रिब्यूनल में

भेजा गया है। दूसरे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत, एक बार जब संसद ने कावेरी बेसिन के पानी के बंटवारे के संबंध में विवाद के फैसले के लिए अधिनियम बनाया है, तो देश में किसी अन्य न्यायालय के पास अंतरिम राहत देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और ट्रिब्यूनल के पास अंतरिम राहत देने की अंतर्निहित शक्तियां हैं, अन्यथा याचिकाकर्ताओं के पास अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई उपाय नहीं बचेगा।

ट्रिब्यूनल ने अधिनियम की योजना की जांच की और अधिनियम की धारा 3 से 6-ए के प्रावधानों का विज्ञापन करने के बाद माना कि जहां तक विवाद के संदर्भ का संबंध है, यह अधिनियम एक पूर्ण संहिता थी। ट्रिब्यूनल को केवल 'जल विवाद' या उसके पास भेजे गए विवादों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। यदि केंद्र सरकार की राय थी कि जल विवाद से जुड़ा या प्रासंगिक कोई अन्य मामला था जिसे पहले ही ट्रिब्यूनल को भेजा जा चुका था, तो यह केंद्र सरकार के लिए हमेशा खुला था कि वह उक्त मामले को भी विवाद के रूप में अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित अधिकरण को संदर्भित कर सके।। ट्रिब्यूनल ने आगे इस प्रकार कहा:

> "जिन अंतरिम राहतों की मांग की गई थी, भले ही वे पहले से संदर्भित जल विवाद से संबंधित हों या प्रासंगिक हों, उन पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त

मामलों के संबंध में विवादों को केंद्र सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल में नहीं भेजा गया है। इसके अलावा, इन याचिकाओं में न तो यह कहा गया है कि अंतरिम राहत से संबंधित विवाद को बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता है और केंद्र सरकार ने पहले ही राय बना ली है कि इसे ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा। मामले में 1990 की सी.एम.पी. संख्या 4, 5 व 9 के याचिकाकर्ता और कर्नाटक राज्य के आचरण से व्यथित हैं और एक आकस्मिक स्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसा कि दावा किया गया है, वे केंद्र सरकार के समक्ष विवाद उठा सकते थे और यदि केंद्र सरकार की राय थी कि उक्त विवाद बातचीत से हल नहीं हो सका, उक्त विवाद को केंद्र सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल में भी भेजा जा सकता था।"

इसके बाद ट्रिब्यूनल ने संदर्भ आदेश दिनांक 2.6.1990 का हवाला दिया और पाया कि तमिलनाडु सरकार के दिनांक 6.7.86 के पत्र में, जो संदर्भ का आधार है, तमिलनाडु राज्य ने निम्नलिखित विवाद को ट्रिब्यूनल में संदर्भित करने की मांग की:

(ए) काबिनी, हेमवती, हरंगी स्वर्णवती और अन्य परियोजनाओं के निर्माण और किसी भी अयाकट का विस्तार करने में कर्नाटक राज्य द्वारा की गई कार्यकारी कार्रवाई:

(i) किस कार्यकारी कार्रवाई के परिणामस्वरूप तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति में भारी कमी आई है;

(ii) किस कार्यकारी कार्रवाई ने पहले से अर्जित और विद्यमान अयाकटदारों के पूर्व-लिखित अधिकारों को भौतिक रूप से प्रभावित किया है; और

(iii) कौन सी कार्यकारी कार्रवाई 1892 और 1924 के समझौतों का भी उल्लंघन है; और

(बी) कावेरी जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित 1892 और 1924 के समझौतों की शर्तों को लागू करने में कर्नाटक सरकार की विफलता।"

उपरोक्त पत्र दिनांक 6.7.86 से ट्रिब्यूनल ने अनुमान लगाया कि तमिलनाडु राज्य द्वारा किए गए अनुरोध की तारीख के बाद साल-दर-साल कर्नाटक सरकार द्वारा पानी छोड़ने के संबंध में कोई अंतरिम विवाद ट्रिब्यूनल को नहीं भेजा गया था। . ट्रिब्यूनल ने इस प्रकार माना कि उनकी राय में ट्रिब्यूनल अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना पर तब तक विचार नहीं कर सकता जब तक कि उससे संबंधित विवाद विशेष रूप से ट्रिब्यूनल को नहीं भेजा गया हो। ट्रिब्यूनल ने तब इस सवाल पर विचार किया कि क्या ट्रिब्यूनल द्वारा अंतरिम राहत देना आकस्मिक या सहायक शक्तियों का प्रयोग होगा। इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के बाद,

ट्रिब्यूनल ने पाया कि आकस्मिक और सहायक शक्तियां संदर्भित वास्तविक विवाद से संबंधित होनी चाहिए, न कि अंतरिम राहत देने सहित किसी अन्य मामले से, जो बिल्कुल भी संदर्भ का विषय नहीं है। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल के पास ऐसे परिणामी आदेश पारित करने की शक्ति होगी जैसा कि उक्त विवाद का निर्णय करते समय किया जाना आवश्यक है और उसके पास आकस्मिक और सहायक शक्तियां भी होंगी जो संदर्भ के निर्णय को प्रभावी बनाएंगी लेकिन ये शक्तियां हैं इसका प्रयोग केवल संदर्भ को प्रभावी ढंग से तय करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन अंतरिम राहत/अंतरिम राहतें देने के संबंध में विवाद सहित संदर्भित नहीं किए गए विवादों पर निर्णय लेने के लिए नहीं। ट्रिब्यूनल ने अधिनियम की धारा 9 और 13 के प्रावधानों के साथ-साथ अंतर-राज्य जल विवाद नियम, 1959 का भी खंडन किया और माना कि ये प्रावधान इस तथ्य के भी संकेत थे कि ट्रिब्यूनल के पास प्रकृति की अंतरिम राहत की अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं थी। इस संबंध में यह देखा गया कि यदि संसद की मंशा यह थी कि न्यायाधिकरण विवाद को ट्रिब्यूनल में भेजे बिना एक अंतरिम राहत के रूप में कोई भी अनुदान देने में सक्षम हो सकता है यह या तो अधिनियम में या अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में ऐसी शक्तियां प्रदान करता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

दूसरे सबमिशन के संबंध में ट्रिब्यूनल ने माना कि यह तर्क देना गलत था कि तमिलनाडु राज्य के पास कोई उपाय उपलब्ध नहीं था, क्योंकि तमिलनाडु राज्य के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का विकल्प खुला था और यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है विवाद पहले से ही ट्रिब्यूनल को संदर्भित जल विवाद से जुड़ा था या उससे संबंधित था, अंतरिम राहत देने के संबंध में उक्त विवाद को भी ट्रिब्यूनल को संदर्भित करने के लिए उसके पास विकल्प खुला था। ऊपर दिए गए विचार में, ट्रिब्यूनल की राय थी कि वह अंतरिम राहत देने के लिए आवेदनों पर विचार नहीं कर सकता।

हमने अपीलकर्ताओं की ओर से श्री के. परासरन और उत्तरदाताओं की ओर से डॉ. चितले और श्री नरीमन द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के विद्वान वकील ने श्री के. परासरन के तर्कों को अपनाया और केरल राज्य के विद्वान वकील ने डॉ. चितले के तर्कों को अपनाया।

दिनांक 2.6.90 के संदर्भ आदेश के अवलोकन से, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने अंतर-राज्य नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवादों को संदर्भित किया था, जो कि तमिलनाडु सरकार के 6 जुलाई, 1986 के पत्र से सामने आया था। इस प्रकार 6 जुलाई, 1986 के पत्र से उभरे सभी विवादों

को ट्रिब्यूनल को भेजा गया था। ट्रिब्यूनल ने उपरोक्त पत्र दिनांक 6.7.86 में निहित निम्नलिखित महत्वपूर्ण पैराग्राफ को पढ़ने में चूक करके गंभीर त्रुटि की है:

विवाद को ट्रिब्यूनल में भेजने के लिए शीघ्र कार्रवाई का अनुरोध:

> "1974-75 के बाद से, कर्नाटक सरकार अपने जलाशयों में सभी प्रवाहों को रोक रही है। उनके जलाशयों के भर जाने के बाद ही, अधिशेष प्रवाह को कम किया जाता है। पिछले दशक में इस राज्य को एकतरफ़ा नुकसान पहुँचाया गया है कर्नाटक की कार्रवाई और हमें हर बार कुछ टीएमसी पानी के लिए इधर-उधर भागना पड़ता था और फसलें सूखने की स्थिति में पहुंच जाती थीं, इसे नोट (संलग्नक-XXVIII) में संक्षेप में बताया गया है। यह स्पष्ट है कि कर्नाटक सरकार ने अंतर का गंभीर उल्लंघन किया है - राज्य ने समझौते किए और इस राज्य में सदियों पुरानी सिंचाई को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। साल-दर-साल यह सामने आया कि मेट्टूर में तेजी से पानी गिर रहा है और बेसिन में हमारे अयाकट में हजारों एकड़ भूमि परती रहने को मजबूर है। तमिलनाडु में मौजूदा अयाकट का बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से तंजावुर और तिरुचिरापल्ली जिलों में

केंद्रित है, जो पहले से ही गंभीर रूप से प्रभावित है क्योंकि खेती के कार्यों में काफी देरी हो रही है, पारंपरिक दोहरी फसल वाली भूमि एकल फसल वाली भूमि में सिमट रही है और यहां तक कि एकल फसल वाली भूमि में भी फसलें उगाई जा रही हैं। महत्वपूर्ण समयों पर पर्याप्त गीलापन के अभाव में सूख रहे हैं और गिर रहे हैं। हम आश्वस्त हैं कि विवाद को सुलझाने में अत्यधिक देरी का फायदा कर्नाटक सरकार ने अपनी नहर प्रणालियों और नई परियोजनाओं में अपने अयाकट का विस्तार करने में उठाया है और हर दिन की देरी से हमारी मौजूदा सिंचाई को होने वाली क्षति बढ़ रही है। "

उपरोक्त अनुच्छेद स्पष्ट रूप से दिखाता है कि तमिलनाडु राज्य तत्काल राहत का दावा कर रहा था क्योंकि साल-दर-साल, मेट्टूर में राजस्व तेजी से गिर रहा था और बेसिन में उनके अयाकट में हजारों एकड़ जमीन परती रहने के लिए मजबूर हो गई थी। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि विवाद को सुलझाने में अत्यधिक देरी का फायदा कर्नाटक सरकार ने अपनी नहर प्रणालियों और नई परियोजनाओं में अपने अयाकट का विस्तार करने में उठाया है और हर दिन की देरी से उनकी मौजूदा सिंचाई को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार ट्रिब्यूनल का यह मानना स्पष्ट रूप से गलत था कि केंद्र सरकार ने कोई अंतरिम राहत देने के लिए

कोई संदर्भ नहीं दिया था। हमें इस बात की चिंता नहीं है कि अपीलकर्ता गुण-दोष के आधार पर किसी अंतरिम ई राहत के हकदार हैं या नहीं, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि अपीलकर्ताओं ने अपने 1990 की सी.एम.पी. संख्या 4, 5 और 9 में जिन राहतों की प्रार्थना की है, स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित विवाद के दायरे में आते हैं। ट्रिब्यूनल ने यह नहीं माना है कि उसके पास अंतरिम राहत देने के लिए कोई आकस्मिक और सहायक शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन उसने सी.एम.पी. संख्या 4, 5 और 9 पर इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया है कि इन आवेदनों में मांगी गई राहतें केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित नहीं की गई थीं। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए हमारा मानना है कि इस मामले में निर्णय लेना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि क्या जल विवाद अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरण के पास कोई अंतरिम राहत देने की कोई शक्ति है या नहीं। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता: हमारे द्वारा उनके पक्ष में दर्ज किए गए निष्कर्ष के आधार पर सफल होने के हकदार हो जाते हैं कि उनके द्वारा अपने 1990 के सी.एम.पी.क्रमांक 4, 5 और 9 में राहत की प्रार्थना की गई थी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा किए गए संदर्भ में शामिल किया गया है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि तर्कों के अंत में कर्नाटक राज्य की ओर से हमारे सामने यह प्रस्तुत किया गया था कि वे सी.एम.पी. के साथ आगे

बढ़ने के लिए सहमत थे। ट्रिब्यूनल के समक्ष योग्यता के आधार पर उन शर्तों पर कि सभी राज्य सभी प्रश्नों पर सहमत हैं जो

जल विवाद (संबंधित पक्षों की संबंधित दलीलों में निर्धारित) से उत्पन्न या उससे संबंधित या प्रासंगिक, जिसमें पार्टी राज्यों द्वारा अंतरिम निर्देशों/राहत के लिए सभी आवेदन शामिल हैं, ट्रिब्यूनल द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। हालाँकि, उपरोक्त शर्तें तमिलनाडु राज्य को स्वीकार्य नहीं थीं, इसलिए हमने गुण-दोष के आधार पर अपीलों पर निर्णय लिया है।

परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के दिनांक 5.1.1991 के फैसले को रद्द कर दिया जाता है और न्यायाधिकरण को 1990 की सी.एम.पी. संख्या 4, 5 और 9 पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हम पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश देते हैं।

सहाय, जे. मैं भाई कासलीवाल, जे. से सहमत हूं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत किसी क़ानून के तहत बनाए गए किसी भी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण की अधिकार क्षेत्र शक्ति और सीमाएं निर्धारित करना इस न्यायालय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है लेकिन मुझे 6 जुलाई, 1986 के पत्र के निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर आपत्ति है।

हालाँकि, मेरे लिए इस पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है क्योंकि जो गहन संवैधानिक और कानूनी महत्व के मुद्दे के रूप में शुरू हुआ था वह ख़त्म हो गया जब कर्नाटक और केरल राज्यों ने अपने वकील के माध्यम से कहा कि वे योग्यता के आधार पर अंतरिम निर्देशों के लिए आवेदनों के निर्धारण के लिए सहमत हैं।

आर.पी. अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमति गुंजन सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमति उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।